जयपुर • कोटा • बीकानेर • उदयपुर • अजमेर • जालोर • हिण्डौनसिटी • चूरू

राष्ट्रदूत

epaper.rashtradoot.com

अजमेर

Rashtradoot

फोनः- 2627612, 2427249 फैक्सः- 0145-2624665 वर्षः 29 संख्याः 244 प्रभात अजमेर, शनिवार 5 अप्रैल, 2025 आर.जे./ए.जे./73/2015-2017 पृष्ठ 6 मूल्य 2.50 रु.

ट्रम्प की टैरिफ घोषणाओं से सभी देशों में भारी आर्थिक उथल-पुथल

सबसे ज्यादा उथल-पुथल अमेरिका में, जहाँ स्टॉक मार्केट में बीस खरब डॉलर की गिरावट आयी

-अंजन रॉय-
-राष्ट्रदूत दिल्ली ब्यूरो-

नई दिल्ली, 4 अप्रैल। ट्रंप के टैरिफ के अगले ही दिन दुनिया हिल गई है। सबसे बड़ा तूफान अमेरिका में देखा गया।

अमेरिका के स्टॉक मार्केट्स में भारी गिरावट आई है और यह गिरावट जारी रहने की संभावना है। बॉन्ड मार्केट, जो स्टॉक्स में विश्वास और निवेश का उल्टा संकेतक होता है, बढ़ रहा है। इसका मतलब है कि निवेशक भविष्य को लेकर चिंतित हैं और एहतियात के तौर पर इक्विटी से बाहर निकलकर सरकारी बॉण्ड में निवेश कर रहे हैं।

स्टॉक मार्केट्स को डर है कि बाजार सर्किट ब्रेकर (एक साथ 7 प्रतिशत से अधिक गिरावट) को छू सकते हैं। जब बाजार इस गिरावट के स्तर तक पहुंचता है, तो सर्किट ब्रेकर स्वतः ही ट्रेडिंग को निलंबित कर देता है। ऐसी घटना एक प्रमख संकट को जन्म दे सकती है।

पिछले दो दिनों में बाजार लगभग 2 ट्रिलियन डॉलर गिर चुका है। यह निवेशकों के लिए एक बड़ा मानसिक झटका है, क्योंकि अब वे इतनी राशि के नुकसान में हैं।

- उथल-पुथल का एक सूचक माना जाता है, पैट्रोलियम के दामों में परिवर्तन। एक दिन में पैट्रोलियम के दामों में 8 प्रतिशत की गिरावट आई है और संभावना है, गिरावट का यह दौर जारी रहेगा।
- परन्तु, इस उथल-पुथल व तूफान के दौर में भारत का स्टॉक मार्केट एक शांत टापू की तरह स्थिरता का प्रतीक बना हुआ है। सैंसेक्स व एन.एस.ई. में गिरावट तो आई है, पर, ऐसा तूफान नहीं मचा है। अतः अंतर्राष्ट्रीय इन्स्टीट्यूशनल पूँजी निवेशक भारत के स्टॉक मार्केट में पूँजी लगाने के लिये आकर्षित होंगे।
- इसी संदर्भ में रिज़र्व बैंक के पूर्व गर्वनर रघुराम राजन ने कहा है कि भारत के लिये ऐसा सुअवसर शायद पीढ़ियों में नहीं आयेगा।
- चीन ने अमेरिका से आयातित होने वाली वस्तुओं पर 34 प्रतिशत टैरिफ लगाया है तथा अमेरिका को ''रेअर अर्थ'' जैसे इलैक्ट्रिक कारों के निर्माण में काम आने वाले खनिज के निर्यात पर प्रतिबंध लगा दिया है।
- यूरोपीय देशों ने भी अमेरिका से आयातित होने वाली वस्तुओं पर भारी टैरिफ लगाने की घोषणा तो की है, पर, अभी तक टैरिफ लगाया नहीं है।
- इस आर्थिक उथल-पुथल के माहौल में अमेरिका के फैडरल बैंक द्वारा ब्याज दर घटाने की भारी चर्चा है, बाज़ार में, स्टॉक मार्केट में निवेश को बढ़ावा देने के लिये। संभवतया भारत का रिज़र्व बैंक भी इस लाइन पर सोच रहा है और वह भी ब्याज़ दर घटाये।

तेल की कीमतों में एक दिन में ही 8 प्रतिशत की गिरावट आई है, जो वैश्विक अर्थव्यवस्था की स्थिरता में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं। उम्मीद है कि मांग में गिरावट के कारण कीमतें और भी कम हो सकती हैं।

तेल की बेंचमार्क कीमत लगभग 60 डॉलर प्रति बैरल पर आ गई है। यह भारत जैसे देशों के लिए अच्छी खबर है, जो तेल की सभी आवश्यकताओं के लिए आयात पर निर्भर करता है।

इस बीच, भारत में अर्थव्यवस्था में स्थिरता कायम है लेकिन पूरी तरह से नहीं। भारतीय बाजारों में मामूली

(शेष अंतिम पृष्ठ पर)

विख्यात अभिनेता मनोज कुमार नहीं रहे

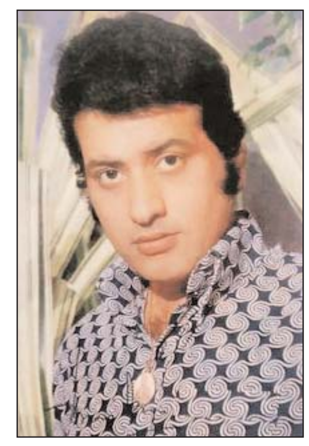

मुंबई, 04 अप्रैल। भारतीय अभिनेता और फिल्म निर्देशक मनोज कुमार का शुक्रवार सुबह निधन हो गया। वे 87 साल के थे। उन्हें अपनी देशभक्ति फिल्मों के लिए जाना जाता था। उनकी देश प्रेम वाली फिल्मों के लिए उन्हें भारत कुमार के नाम से भी जाना जाता था। उन्होंने कोकिलाबेन धीरूभाई अंबानी अस्पताल में अंतिम सांस ली। इस खबर के बाद पूरे देशमें शोक की लहर है। दोपहर बाद विशाल टावर, जुहू में उनके अंतिम दर्शन किए जा सकेंगे। कल सुबह पवन हंस श्मशान घाट, जुहू में उनका अंतिम संस्कार किया जाएगा।

- देशभक्ति फिल्मों के कारण भारत कुमार नाम से प्रसिद्ध 87 वर्षीय मनोज कुमार का हार्ट अटैक से निधन हो गया।

(शेष अंतिम पृष्ठ पर)

लोकसभा व राज्यसभा में पारित वक्फ संशोधन विधेयक को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती

गृह मंत्री अमित शाह व संसदीय मामलों के मंत्री किरण रिजीजू ने पार्टी की सोच को पुरजोर ढंग से पेश किया कि विधेयक वक्फ बोर्ड के संचालन में व्याप्त भ्रष्टाचार पर नियंत्रण करने के लिये लाया गया है

-डॉ. सतीश मिश्रा-
-राष्ट्रदूत दिल्ली ब्यूरो-

नई दिल्ली, 4 अप्रैल। विवादास्पद वक्फ संशोधन बिल 2025, जिसे संसद ने मंजूरी दे दी है, को शुक्रवार को कांग्रेस सांसद मोहम्मद जावेद और ऑल इंडिया मजलिस-ए- इत्तेहादुल मुसलमीन के असदुद्दीन ओवैसी ने सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी।

बिल जो राष्ट्रपति मुर्मू के हस्ताक्षर के बाद कानून बन जाएगा, को देश की सबसे बड़ी अदालत में साथ ही जनता की अदालत में भी चुनौती दी जाएगी, जिसकी पहली परीक्षा बिहार के चुनावों में होगी जो इसी वर्ष अक्टूबर -नवम्बर में होने जा रहे हैं। देखना यह है कि दोनों अदालतों में इस कानून के बारे में क्या फैसला आता है।

वक्फ बिल गुरुवार को राज्यसभा में पारित हो गया, जहां इसके पक्ष में 128 और विपक्ष में 95 वोट पड़े। इससे पहले लोकसभा में यह बिल 232 के मुकाबले 288 मतों से पारित हो गया।

दोनों सदनों में काफी रोचक बहस हुई जिसमें विपक्षी सदस्य विजेता बनकर उभरे सत्ता पक्ष के सदस्य पर पार्टी लाइन दोहराते रहे और बिल के बचाव में भ्रष्टाचार का मुद्दा उठाते रहे। इनमें केन्द्रीय गृहमंत्री अमित शाह और संसदीय कार्यमंत्री किरेन रिजीजू प्रमुख थे।

विपक्षी खेमे से दो बड़े वकीलो, कपिल सिब्बल और अभिषेक मनुसिंघवी, ने राज्यसभा की बहुत भारी आलोचना की। कांग्रेस के सिंघवी ने कहा कि अगर इस बिल को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी गई तो पूरी संभावना है कि न्याय पालिका इसे असंवैधानिक घोषित कर दे।

- विपक्ष की ओर से कपिल सिब्बल व अभिषेक मनु सिंघवी ने विधेयक की कमियाँ व त्रुटियाँ उजागर करने में प्रभावशाली भूमिका निभाई।
- अभिषेक मनु सिंघवी ने कहा, भारी संभावना है कि न्यायपालिका इस विधेयक को असंवैधानिक (अनकॉस्टिट्यूश्नल) घोषित करेगी।
- सिब्बल ने कहा कि इस बात पर भारी चर्चा हुई कि वक्फ बोर्ड के पास बहुत जमीनें हैं, पर, यह भी उल्लेखनीय है कि दक्षिण भारत के चार राज्यों में ही हिन्दू मंदिरों के पास दस लाख एकड़ भूमि है।
- उन्होंने (सिब्बल ने) यह आपत्ति भी उठाई कि हिन्दू मन्दिरों के ट्रस्ट के मैनेजमैंट के निर्णय को तो आप फाइनल मानते हैं, पर, आपको यह मान्य नहीं है कि वक्फ ट्रिब्युनल का दिया गया निर्णय भी फाइनल है।

(शेष अंतिम पृष्ठ पर)

स्टालिन ने एक और भावात्मक मुद्दा ढूंढ निकाला आगामी विधानसभा चुनाव के लिये

स्टालिन के नेतृत्व में तमिलनाडु ने दावा किया, मेडिकल शिक्षा में तमिलनाडु बहुत आगे है, और अपने इस शिक्षा के क्षेत्र की सफलता जारी रखने के लिये, स्टालिन मेडिकल कॉलेजों में प्रवेश के लिये ''नीट'' से मुक्ति चाहते हैं

-लक्ष्मण वैंकट कुची-
-राष्ट्रदूत दिल्ली ब्यूरो-

नई दिल्ली, 4 अप्रैल। जिस दिन भाजपा की तमिलनाडु इकाई के अध्यक्ष के. अन्नामलाई ने पार्टी के नेता पद से हटने की घोषणा की, उसी दिन केन्द्र की भाजपा सरकार ने, अगले वर्ष होने वाले राज्य विधानसभा चुनावों से पहले, द्रमुक प्रमुख तथा राज्य के मुख्यमंत्री एम.के. स्टालिन को एक और भावनात्मक मुद्दा थमा दिया, जिसका दोहन वे चुनावों में कर सकें।

अन्नामलाई, जो अन्नाद्रमुक के एनडीए से बाहर होने के प्रमुख कारण थे, ने शुक्रवार को पत्रकारों को बताया कि वे पार्टी के हितचिन्तक हैं, तथा इसके बाद उन्होंने भाजपा के प्रदेशाध्यक्ष पद की दौड़ से स्वयं को अलग रखने की घोषणा कर दी। जैसा कि पिछले सप्ताह की रिपोर्टिंग में, राष्ट्रदूत में बताया गया था, अन्नामलाई का हटना अन्नाद्रमुक नेतृत्व की गठबंधन को पुनर्जीवित करने की पूर्व-शर्त थी।

जहां गठबंधन के मुद्दे पर कुछ आगे बढ़ने की स्थिति की संभावना हो सकती है, वहीं भाजपा द्रमुक नेता को मुद्दे पर मुद्दे देती जा रही है, एनईईटी (नीट) ऐसा ही एक मुद्दा है। तमिलनाडु

- स्टालिन ने विधानसभा में कहा, तमिलनाडु ''नीट'' से मुक्ति के लिये दो बार सर्वसम्मति से ''नीट'' परीक्षा के खिलाफ प्रस्ताव पारित कर चुका है। पर, केन्द्रीय सरकार उनके प्रस्ताव को स्वीकार नहीं कर रही है। यह तमिलनाडु के विद्यार्थियों के प्रजातंत्रीय अधिकारों व महत्वाकांक्षा के खिलाफ है।

(शेष अंतिम पृष्ठ पर)

युद्ध विधवा को 11 साल बाद भी भूमि आवंटन क्यों नहीं हुआ?

जयपुर, 4 अप्रैल। राजस्थान हाईकोर्ट ने 1965 की युद्ध विधवा को 11 साल में भूमि आवंटित नहीं करने को लेकर प्रमुख राजस्व सचिव से शपथ पत्र पेश करने को कहा है। अदालत ने प्रमुख राजस्व सचिव से पूछा है कि उसे पूर्व में आवंटित की गई जमीन का आवंटन रद्द करने के बाद, अब तक दूसरी भूमि आवंटित क्यों नहीं की गई। जस्टिस महेन्द्र गोयल की एकलपीठ ने ये आदेश धरियाव कंवर की याचिका पर सुनवाई करते हुए दिए। अदालत ने स्पष्ट किया है कि यदि चार सप्ताह में मामले को लेकर आवश्यक कार्रवाई कर ली जाती है तो प्रमुख राजस्व सचिव को शपथ पत्र पेश करने की आवश्यकता नहीं है।

- हाई कोर्ट ने चार सप्ताह में आवंटन की सभी कार्यवाही पूरी करने के निर्देश दिये।

याचिका में अधिवक्ता ओपी मिश्रा ने अदालत को बताया कि याचिकाकर्ता के पति भारतीय सेना में थे और साल

(शेष अंतिम पृष्ठ पर)

नीतीश कुमार द्वारा वक्फ बोर्ड विधेयक को समर्थन देने से, जद (यू) के कई मुस्लिम नेताओं का पार्टी से पलायन!

पांच वरिष्ठ पार्टी नेताओं ने जद (यू) की सदस्यता त्यागी, तथा दो अन्य बड़े नेताओं ने समर्थन पर विरोध दर्ज कराया

-डॉ. सतीश मिश्रा-
-राष्ट्रदूत दिल्ली ब्यूरो-

नई दिल्ली, 4 अप्रैल। जेडी (यू) द्वारा वक्फ संशोधन विधेयक का समर्थन किये जाने के कारण पार्टी के मुस्लिम नेताओं में असंतोष बढ़ रहा है और अब तक 5 वरिष्ठ नेताओं ने इस्तीफे दे दिये हैं तथा दो वरिष्ठ नेताओं ने पार्टी के इस निर्णय के खिलाफ अपना विरोध दर्ज करा दिया है।

वरिष्ठ नेता मुहम्मद कासिम अंसारी, बिहार के जेडी (यू) अल्पसंख्यक प्रकोष्ठ के सचिव मुहम्मद शाहनवाज मलिक, जेडी (यू) अल्पसंख्यक प्रकोष्ठ के स्टेट जनरल सेक्रेटरी मुहम्मद तबरेज सिद्दीकी अलीग, जेडीयू यूथ विंग के पूर्व स्टेट सैक्रेटरी एम. राजू नय्यर तथा नदीम अख्तर ने अपने त्याग पत्र भेज दिये हैं।

पार्टी में सबसे पहले इस्तीफा देने वाले वरिष्ठ नेता मुहम्मद कासिम अंसारी थे। उन्होंने आरोप लगाया कि इस विधेयक का समर्थन करके नीतीश कुमार ने मुस्लिम समुदाय को बहुत बड़ा आघात पहुँचाया है।

अपने त्याग पत्र में अंसारी ने कहा कि वे इस विधेयक को किसी भी कीमत पर स्वीकार नहीं कर सकते। इस विधेयक के जरिये मुस्लिमों का अपमान किया गया है। उन्होंने इतने सालों तक जेडी (यू) में बने रहने के लिये अफसोस व्यक्त किया।

जेडी (यू) बिहार अल्पसंख्यक प्रकोष्ठ के सेक्रेटरी मुहम्मद शाहनवाज मलिक ने अपने इस्तीफे की घोषणा करते हुये, शुक्रवार को पार्टी अध्यक्ष नीतीश कुमार को पत्र लिखकर कहा कि वे (नीतीश कुमार) मुस्लिमों का पूरा विश्वास खो चुके हैं, जो ये मानते थे कि पार्टी धर्मनिरपेक्ष है।

पत्र में मलिक ने लिखा है, ''हमारी तरह, भारत के करोड़ों लोगों को यह दृढ़ विश्वास था कि आप पूरी तरह धर्मनिरपेक्ष विचारधारा के झंडाबरदार हैं। लेकिन अब यह विश्वास टूट गया है।'' जेडी (यू) अल्पसंख्यक प्रकोष्ठ के स्टेट जनरल सेक्रेटरी मुहम्मद तबरेज सिद्दीकी अलीग पार्टी से इस्तीफा देने वाले तीसरे शीर्ष नेता हैं।

- इन मुस्लिम नेताओं ने नीतीश कुमार को चिट्ठी लिखकर कहा, ''लाखों मुस्लिम मतदाताओं ने आपको बार-बार मु.मंत्री की कुर्सी पर बैठाया, आज आपने उनका विश्वास खो दिया है।''
- जद (यू) के एक अन्य मुस्लिम नेता ने कहा, ''मुसलमानों को ठोस कदम उठाने का समय आ गया है। उन्हें अपने अधिकारों के लिये लड़ना पड़ेगा, और केवल सोशल मीडिया में नहीं।''

(शेष अंतिम पृष्ठ पर)

पीएचईडी चीफ इंजीनियर जमानती वारंट से तलब

जयपुर, 4 अप्रैल। राजस्थान हाईकोर्ट ने अदालती आदेश की पालना में पीएचईडी के चीफ इंजीनियर, राकेश लुहाड़िया के अदालत में पेश नहीं होने पर नाराजगी जताई है। इसके साथ ही, अदालत ने आगामी सुनवाई पर उनकी उपस्थिति सुनिश्चित करने के लिए उन्हें पांच हजार रुपए के जमानती वारंट से तलब किया है। जस्टिस नरेन्द्र सिंह की एकलपीठ ने यह आदेश परमेश्वर कुमार शर्मा व अन्य की ओर से दायर अवमानना याचिकाओं पर सुनवाई करते हुए दिए।

- हाई कोर्ट ने यह आदेश अवमानना याचिकाओं पर सुनवाई करते हुए दिये।

याचिका में अधिवक्ता सीपी शर्मा ने अदालत को बताया कि याचिकाकर्ताओं ने राजस्थान सिविल सेवा अपीलीय अधिकरण में अपील दायर कर साल 2014 की वरिष्ठता

(शेष अंतिम पृष्ठ पर)

'अंतरराष्ट्रीय व्यापार में, उथल-पुथल व अराजकता प्रथम अध्याय होता है सुअवसर (ऑपरच्युनिटी) का'

अमेरिका से बातचीत व सौदेबाजी करने के मकसद से वॉशिंगटन गई टीम के एक वरिष्ठ अधिकारी ने ट्रम्प द्वारा भारत से आयातित वस्तुओं पर लगाये गये 26 प्रतिशत टैरिफ के बारे में सटीक टिप्पणी की

-सुकुमार साह-
-राष्ट्रदूत दिल्ली ब्यूरो-

नई दिल्ली, 4 अप्रेल। ''ग्लोबल व्यापार में उथल-पुथल व अराजकता, अक्सर सुअवसर का पहला अध्याय होता है।'' भारत के एक वरिष्ठ ट्रेड अधिकारी ने, अमेरिका द्वारा भारत के विभिन्न वस्तुओं के आयात पर लगाए गए 26 प्रतिशत टैरिफ को उक्त शब्दों में समझाया। गुरुवार को वॉशिंगटन द्वारा की गई यह घोषणा ग्लोबल सप्लाई चेन्स (आपूर्ति श्रृंखलाओं) को हिलाकर रख सकती है। भारत, हालांकि, इससे अछूता नहीं है तथा यदि वह अपने पत्ते सही तरीके से खेलता है तो और अधिक मजबूत हो सकता है।

- अरनैस्ट एण्ड यंग के टैक्स पार्टनर विपिन सपरा ने इस बारे में कहा कि भारत की कई अन्य देशों से स्थिति बेहतर है तथा अमेरिका से आपसी व्यापार समझौता (बाईलेटरल ट्रेड एग्रीमैंट) करके भारत इन टैरिफ के झटकों को अपनी व्यापारिक रणनीति से सुअवसर में परिवर्तित कर सकता है।
- उदाहरण के लिये भारत को कड़ा संघर्ष करना पड़ेगा, स्वर्ण आभूषण के निर्यात में, क्योंकि मिडिल ईस्ट को, 17 प्रतिशत टैरिफ कम लगने का ''एडवांटेज'' है। पर, भारत को थाईलैण्ड के मुकाबले 10 प्रतिशत टैरिफ का लाभ है, चाँदी व हीरे के आभूषणों के निर्यात में।
- इसी प्रकार से भारत के गलीचे निर्यात करने वाले व्यापारियों को टर्की के गलीचे निर्माताओं के मुकाबले 16 प्रतिशत ज्यादा टैरिफ लगने का खामियाज़ा भुगतना पड़ेगा।
- अचानक भारत के परिधान निर्यात करने वाले टैक्सटाइल ट्रेडर्स की आँखों में चमक आ गई है, क्योंकि चीन व वियतनाम से निर्यात होने वाला माल, अधिक टैरिफ लगने से अमेरिका के बाज़ार में और महँगा हो गया है।

पाँच से नौ अप्रेल के बीच लगाए जाने वाले नए यू.एस. शुल्क मौजूदा कस्टम शुल्क के ऊपर लगाए गए हैं और फार्मास्युटिकल्स तथा ऑटोमोबाइल जैसी उन वस्तुओं को छूट दी गई है, जिन पर पहले रज़ामंदी हो चुकी है। इसका प्रभाव संपूर्ण उद्योग पर पड़ेगा, लेकिन एक समान नहीं। जहाँ, भारत के श्रिंप (झींगा) तथा गोल्ड जूलरी निर्यात पर सीधा असर पड़ेगा, वहीं इलैक्ट्रॉनिक्स, टैक्सटाइल, प्लास्टिक और कैमिकल जैसे सैक्टरों को भारी लाभ हो सकता है, क्योंकि इस क्षेत्र में भारत को प्रतिस्पर्धा देने वाले देशों की हालत और ज्यादा खराब है।

ई.वाय. इण्डिया में टैक्स पार्टनर विपिन सापरा ने कहा, ''गलतफहमी में मत रहिए, टैरिफ परिदृश्य में ये भारी परिवर्तन हैं। लेकिन भारत अधिकांश देशों की तुलना में बेहतर स्थिति में है। अमेरिका के साथ द्विपक्षीय व्यापार समझौता इन टैरिफ झटकों को एक रणनीतिक अवसर में बदल सकता है।''

(शेष अंतिम पृष्ठ पर)

भजनलाल ने प्रधानमंत्री, गृह मंत्री का आभार जताया

जयपुर, 4 अप्रेल। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने 'वक्फ (संशोधन) विधेयक-2025' के संसद के दोनों सदनों में बहुमत से पारित होने पर समस्त देशवासियों को हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं दी हैं। उन्होंने कहा कि यह विधेयक देश के प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के 'सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास' के संकल्प का प्रमाण होने के साथ ही, देश में समानता, पारदर्शिता और सुशासन को मजबूत करने की दिशा में एक ऐतिहासिक कदम है। मुख्यमंत्री ने इस अभूतपूर्व विधेयक के लिए देश के प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी व केन्द्रीय गृह मंत्री अमित शाह का आभार जताया।

- मुख्यमंत्री ने कहा, वक्फ संशोधन विधेयक गरीब व जरूरतमंदों को सशक्त बनायेगा।

मुख्यमंत्री ने कहा कि वक्फ

(शेष अंतिम पृष्ठ पर)